सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 1/2019

दिनांक : 01/1/2019

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

विषय : अभिनंदन, नववर्ष 2019

प्रिय साथियों ,

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन की ओर से हम नये वर्ष के अवसर पर, समस्त बीमा कर्मियों के साथ-साथ देश-प्रदेश के तमाम मेहनतकश अवाम को लाखों-लाख क्रांतिकारी अभिनंदन एवं बधाई प्रेषित करते हैं।

वर्ष 2018 हर स्तर पर बहुत ही उतार-चढ़ाव वाला दौर रहा है। एक ओर आम जनता के अलावा मेहनतकश वर्ग पर आक्रमण तीखा हुआ है तो दूसरी ओर उसके खिलाफ प्रतिरोध भी तीव्र हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, हर स्तर पर इसकी झलक स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब मुनाफा ही सर्वोपरि रहेगा तो इसका खामियाजा केवल आम जनता और मजदूर वर्ग पर ही पड़ना लाजिमी है, जिससे वैश्विक स्तर पर असमानता बढ़ी है। इस व्यवस्था के खिलाफ दुनिया भर में प्रतिरोध के स्वर तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। अभी हाल के दिनों में फ्रांस में इसका नजारा देखने को मिला, जब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आयी और सरकार को पीछे हटना पड़ा। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट से प्रारंभ हुए घटनाक्रम की गूंज समूचे यूरोप में जनअसंतोष की अभिव्यक्ति के रुप में दिख रही है। इससे यह साफ है कि एकजुट संघर्ष से किसी भी सरकार की गलत नीति, जो आमजन से जुड़ी हुई हों, जनता बदलने के लिए बाध्य कर सकती है। इसलिए विश्व के पैमाने पर जनता संगठित होकर साम्राज्यवादी जनविरोधी नीतियों को बदलने के लिए लगातार संघर्षरत है। अमेरिका की हालत हमसे छिपी नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नीतियां बनाकर लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। अभी हाल ही में एफबीआई के पूर्व प्रमुख ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एफबीआई के संबंध में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। झूठा बयान देना, वो भी जानबूझकर अब इसका भी वैश्वीकरण हो गया है। इस रोशनी में यह साफ है कि वर्ष 2019 जनता के लिए एक संघर्ष का ही पैगाम दे रहा है , जो निश्चय ही आगे और तीव्र होगा।

राष्ट्रीय परिस्थिति का अवलोकन वर्ष 2018 का करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि देश की सत्ता जिनके हाथ में है, उसे मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसी की भी परवाह नहीं है। हर तरफ अराजकता का माहौल है संविधान हो या लोकतंत्र या अन्य संवैधानिक संस्थाएं, इनके निशाने पर हैं। जिस नरेन्द्र मोदी की सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत प्रदान किया था, जिसने यह वादा किया था, कि देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, जनता के प्रत्येक बैंक खाते में 15 लाख जमा होगा, किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, देश से भ्रष्टाचार का नामो-निशान नहीं रहेगा। लेकिन आज साढ़े चार वर्ष में इसके उलट बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, मंहगाई अपने चरम स्तर पर है, किसानों की आत्महत्या के मामले निरंतर पूरे देश के पैमाने पर बढ़ रहा है। महिलाओं पर अत्याचार में लगातार वृद्धि हो रही है, दलितों पर आक्रमण और तेज हुआ है और भीड़ की हिंसा के नाम पर निर्दोष की खुलेआम जान ली जा रही है।

धर्म और संप्रदाय के नाम पर खुलेआम दहशतगर्दी का माहौल व्याप्त है। भीड़तंत्र द्वारा सुनियोजित हमला, सरकार द्वारा प्रायोजित और संरक्षित है। इतना ही नहीं सबसे चिंताजनक स्थिति तो यह है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है उसकी बानगी इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली है। मामला चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि हो या सीबीआई का, चुनाव आयोग की हो या प्रवर्तन निदेशालय का, हर संस्थानों को तहस-नहस किया जा रहा है। इतना सब हो रहा है मगर सरकार खामोश है, मौन है क्योंकि यह उसी के इशारे पर हो रहा है और मानो उसे तो पता है कि यही सब करने के लिए वे सत्ता पर काबिज हैं। संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की

आजादी हो या न्यायपालिका, विधायिका या फिर उच्च शिक्षा संस्थान जैसी संस्था सब कुछ निशाने पर है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रजातांत्रिक अधिकारों का ऐसा दमन आजाद भारत के इतिहास में, यहां तक कि घोषित आपातकाल के दौर में भी देखने नहीं मिला था। यहां तक कि रफाल सौदे हो या बैंक के एनपीए, बैंक का धन लूटकर भागे भगौड़े पर सवाल हो या नोटबंदी, जीएसटी की मार से अर्थव्यवस्था में गहराते संकट पर उठते सवाल, अगर आपने सवाल पूछा तो देशद्रोही की श्रेणी में खड़े कर दिये जाओगे। आतंक और अराजकता का यह दौर अकल्पनीय है।

लेकिन देश की जनता पर जब-जब आक्रमण होता है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिशें होती हैं तब-तब यही जनता पूरे जोश के साथ एकजुट होकर सत्ता के मद में चूर चाहे फिर कोई भी सरकार हो, उसे उसकी हैसियत जरूर याद दिला देती है और ऐसा ही हुआ जब वर्ष 2018 की विदाई बेला में देश के पांच राज्यों का चुनाव, जो अभी हाल में सम्पन्न हुआ, उसमें देश की जनता ने स्पष्ट तौर पर सरकार के छद्म ऐजेण्डा को ठुकराकर रोजगार, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं और दलितों पर आक्रमण और अपने जीवन के मुद्दों को अहमियत देते हुए मप्र, छग व राजस्थान में मौजूदा भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का जनादेश दिया।

अवाम ने जता दिया है कि सरकार मंदिर-मस्जिद के नाम पर कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदु-मुस्लिम के नाम दंगा भड़काने का कितना भी उपाय करे, दलितों और सवर्ण के बीच कितना भी खाई चौड़ी करने की कोशिश कर ले हमारा मुद्दा तो, नौकरी, महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, आपसी भाई-चारा और एकता ही रहेगा और इसी मुद्दे को लेकर आगामी लोकसभा का चुनाव भी रहेगा। आजाद भारत के इतिहास में 2018 का साल अनगिनत जनसंघर्षों के उबाल का साल रहा है। निश्चय ही आम जनता की इसी शक्ति के बल पर मजदूर-किसान-छात्र-युवा महिलाओं के उभरते संघर्षों की दिल्ली तक पहुंची तपिश वर्ष 2019 में दावानल बनेगी।

राष्ट्रीयकृत भारतीय जीवन बीमा निगम अपने जन्म से लेकर आज तक उन्नति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2018 में भी उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहा। बावजूद इसके कि बाजार में अन्य निजी बीमा कंपनी प्रतिस्पर्धा में है, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं राष्ट्रीयकृत आम बीमा का आज भी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सरकार की नीति बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकृत स्वरूप को मजबूत करना नहीं बल्कि अंततः इसे निजी हाथों में सौंपने की है। बीमा कर्मचारी एआईआईईए के नेतृत्व में निजीकरण के विरुद्ध लगातार अपने संघर्षों को आम जनता के बीच ले जाकर जनमानस को लामबंद कर रहे हैं। हमें नववर्ष में इसे और आगे बढ़ाना होगा।

बीमा कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारण 1 अगस्त 2017 से देय है, लेकिन अफसोस आज तक न प्रबंधन ने और न ही सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल की गई है। इसके अतिरिक्त पेंशन का एक अंतिम विकल्प की मांग भी लंबित है। प्रबंधन सैद्धांतिक तौर पर सहमत होते हुए भी वर्तमान सरकार से इसके लिए स्वीकृति नहीं ले सकी है। इस वजह से पूरे देश के बीमा कर्मचारियों के अंदर जबर्दस्त रोष है। वेतन वार्ता प्रारंभ करने, पेंशन का एक अंतिम विकल्प, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अविलंब भर्ती प्रारंभ करने के लिए संघर्ष का दौर जारी है। नव वर्ष में हमें इसके सार्थक समाधान प्राप्त करने तीव्र रूप से जुटना होगा।

बीमा कर्मचारियों के अलावा पूरे देश के पैमाने पर सरकार की मजदूर विरोधी/कर्मचारी विरोधी जन विरोधी नीति को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न मजदूर संगठनों के आह्वान पर नववर्ष का आगाज 8 एवं 9 जनवरी 2019 को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हो रहा है। इस हड़ताल में बीमा कर्मचारियों के अलावा केन्द्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, हर हिस्से के श्रमिक भी शामिल हैं।

नये साल के प्रारंभ में ही इस हड़ताल के आगाज से केन्द्र की सरकार को मेहनतकश जनता स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि, मेहनतकशों को चाहिए एक बेहतर जीवन और उनकी एकता को धर्म, भाषा, जाति, सम्प्रदाय के नाम से विभाजित करने की साजिश नहीं चलने वाली है। समाज को बांटने का षड़यंत्र सफल नहीं होने वाला , इस उम्मीद के साथ हम नव वर्ष, 2019 का पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं कि आने वाला वक्त केवल और केवल मेहनतकशों, मजदूर, किसानों का होगा।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव